

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक ०५ जनवरी, 200४

विषय:- राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में देहरादून के अन्तर्गत लूनिया मौहल्ला (वार्ड सं० 35) एवं समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1859/अप्रेजल-देहरादून/दिनांक 19.06.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत देहरादून के लूनिया मौहल्ला (वार्ड नं०-35) एवं समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल योजना अनु०लागत रु० 184.27 लाख के प्राक्कलन पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु० 176.08 लाख (रु० एक करोड़ छियत्तर लाख आठ हजार मात्र) के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 50.00 लाख (रु० पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार दो समान किस्तों में आहरित की जायेगी । प्रथम किस्त के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किस्त आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी ।

3- आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित करने के लिए अनुमन्य हैं । कार्य कराने से पूर्व दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी । बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गई है ।

6- एक मुस्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

- 7- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करे।
- 8- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व गानको एवं रतोर परचेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।
- 9- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल की भलीभाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- 10- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 11- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/गुट-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।
- 12- स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यों पर व्यय की जायेगी उन कार्यों की लागत के सापेक्ष उ० प्र० शासन की वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-87 (1) दस-97-17(4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सैटेज चार्ज के रूप में अनुमन्य होगी।
- 13- उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय धनराशि के विवरण की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति मासिक रूप से यथासमय शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति न हो अथवा जो विवादग्रस्त है। धन का उपयोग उन्हीं योजनाओं पर किया जाय जिनके लिये स्वीकृति दी जा रही है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय।
- 14- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक अथवा इसके पूर्व ही उपयोग कर लिया जाय ताकि योजना शीघ्र पूर्ण होकर उसका लाभ शीघ्र जनता को प्राप्त हो। उक्तानुसार पूर्ण उपयोग व कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही देय अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 16- जीपीडब्लू फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- 17- योजना समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जायेगी तथा किसी भी दशा में योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन मान्य नहीं होगा।
- 18- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत -101- शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये अनुदान-20-सहायक अनुदान/ अंशदान राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 717/XXVII (2)/08 दिनांक 01 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(टीकम सिंह पवार)
संयुक्त सचिव

सं० 359/उन्तीस(2)-2(60⁹²मे०)/2007, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सेल)/राज्य योजना आयोग, उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
9. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 11. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(नवीन सिंह तडागी)
उप सचिव
5/1/08